

सम्पादकीय

सजा ही लगाएगी निरंकुशता पर अंकुश
ज के दिनों में देश के विभिन्न भागों में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा

व्यवहार की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। निःसंदेह, गौतम तस्करी करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन कानून के तहत गौधन की खरीददारी करने वालों को यदि हिंसक भीड़ का शिकार होना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा। ऐसे मामलों में पुलिस की सतर्कता और कानून की सख्ती ही किसी निरंकुश व्यवहार पर रोक लगा सकती है। ऐसे ही हरियाणा के नूँह जिले के रकबर खान की गौतम तस्करी के संदेह में भीड़ द्वारा हत्या करने की घटना सामने आई थी। जुलाई 2018 में जब रकबर अपने एक साथी के साथ गौधन खरीदकर अलवर से हरियाणा लौट रहा था तो स्थानीय लोगों ने उन्हें पीटा था।

इस घटना में रकबर ने पिटाई के बाद दम तोड़ दिया था। इस

ठटनाक्रम के पांच साल बाद अलवर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने चार गौरक्षकों को सात साल की सजा सुनाई है। निस्संदेह, सजा ही ऐसे मामलों में कानून हाथ में लेने की प्रवश्ति पर अंकुश लगाएगी। अलवर जनपद में 2017 में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जिसमें डेयरी किसान पहलू खान तब हिंसा का शिकार बना जब वह साप्ताहिक बाजार से मर्वेशियों को नूंह में अपने गांव ले जा रहा था। लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छह आरोपियों को सत्र अदालत ने बरी कर दिया था। आरोपियों को पुलिस जांच के आधार पर संदेह का लाभ मिला था। अदालत ने भी जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। उल्लेखनीय है कि रकबर खान के प्रकरण में आरोपियों को सजा सुनाने का मामला तब सामने आया है जबकि राजस्थान पुलिस ने बहुचर्चित जुनैद व नासिर हत्या मामले में मानू मानेसर समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल, यह जांच भिवानी जिले में इन दोनों के शव पाये जाने के बाद शुरू हुई थी। तब भी आशंका जतायी जा रही थी कि पुलिस की चूक के बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था।

पुलिस का ढलाइ के चलत हा गोरक्षक कानून अपन हाथ म लन लग जाते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि गौधन की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देश में दोषियों को सजा देने के लिये एक पूरा कानूनी सिस्टम बना हुआ है। आशंका जतायी जाती रही है कि गौरक्षा के नाम पर असामाजिक तत्व डेयरी किसानों व पशु व्यापारियों के खिलाफ हिंसा करते हैं। निस्संदेह, तस्करों से निवटने का अधिकार सिर्फ पुलिस को है न कि हिंसक भीड़ को। वहीं हिंसा का सहारा लेने वाले समूहों पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी कानून लागू करने वालों की है। इसमें दो राय नहीं कि गौरक्षकों के नाम पर सक्रिय असामाजिक तत्वों तथा उन्हें संरक्षण देने वालों पर शिकंजा कसना जरूरी है।

जश्न की तैयारी



और इस मौके पर एक महीने के अंतर्शन की शुरुआत होगी। अगले एक महीने भाजपा पूरे देश में मोदी सरकार के कामकाज का प्रचार बढ़ाव देगी। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी के नेता बताएंगे। राज्यों के हिसाब से केंद्र सरकार की उपलब्धियों की सूची बनाई जा ही है। सरकारी पोर्टल माई गॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश विप्राठी ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिख कर उनसे उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी है। उन योजनाओं पर अमल से क्या बदलाव हुआ और लोगों को क्या फायदे हुए हैं इसकी सूची भी बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से प्रचार की अलग रणनीति बनी है तो भाजपा की ओर चार की अलग रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी पूरे देश में कार्यक्रमों का योजन करेगी। इसकी शुरुआत 31 मई को राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से हो रही है। इस रैली में आसपास के कई राज्यों के लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और झज्जीसगढ़ में भी चुनाव हैं और बताया जा रहा है कि उन राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो सकती हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता पूरे देश में 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे। भाजपा ने जिला स्तर से लेकर बूथ तक कार्यक्रम करने का प्लान बनाया है। 30 मई से भाजपा का संपर्क अभियान शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा।

वार क्या पद लाकरत्र



थी, आपकिस्त
हो गये
के उस
वक्त भी
वतन
स्वीकार
के लिए
जीने के
संविधान
कारण
हुआ।
लोकतं
हैं। आप
ने कई
तरह

जादी के बाद भी वैसी ही रहती। तान तो धर्म के आधार पर अलग था और बहुत से लोग सीमा पार चले गए थे। मगर उस बहुत से मुसलमानों ने अपने यानी हिंदुस्तान को छोड़ना इच्छा किया। ऐसे तमाम लोगों एवं बराबरी के, सम्मान के साथ अवसर बने रहे, इसकी व्यवस्था न में की गई। इन अधिकारों के ही भारत का लोकतंत्र मजबूत पुराने संसद भवन की दीवारें त्र के सशक्त होने की गवाह रही जादी के बाद की सभी सरकारों तरह की गलतियां की, कई वै अपार्टमेंट कर्स वाले नेतिकाताओं, रखा गया। म लोकतंत्र के टिकी रहे, य भाजपा के बिहारी वाजे आएंगी, जाएं चाहिए। वे उ लोकतंत्र के इसलिए चाहे बात उन्होंने जड़ें को उस कभी नहीं फ जनता की अ में चुनिंदा वै रेप्रेसेंटेंट रहे।

मर्यादाओं को ताक पर
गर सारे ज़ङ्गावात के बीच
पेड़ की जड़ें जगह पर
हुनिश्चित किया गया।
ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल
बिहारी ने कहा था कि सरकारें
गी, मगर ये देश बना रहना
अच्छे से जानते थे कि देश
बिना बना नहीं रहेगा।
जैसे जमीन समतल करने की
कही हो, लोकतंत्र की
खड़ने की मंशा उन्होंने भी
दिखाई। पुरानी संसद में
वाज गूंजती थी, नई संसद
यस ओवर चलाए जाएंगे।

नीति आयोग और राज्य सरकारे

है। इसके बावजूद योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की मार्फत ही 1990 तक लगातार आर्थिक तरक्की करता रहा और यह एक औद्योगिक राष्ट्र बना तथा इसके समाज में बहुत बड़े मध्यवर्गीय उपभोक्ता श्रेणी का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान की गई तरक्की के बूते पर ही भारत 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों के लिए खोलने की हिम्मत जुटा सका क्योंकि तब तक भारत का निजी उद्योग इस काबिल बन चुका था कि वह विदेशी प्रतियोगिता के सामने टिक सके। भारत की इस अपार क्षमता को देख कर ही विदेशी कम्पनियां 1991 के बाद से इस देश में निवेश करने को आतुर हुईं क्योंकि उन्हें भारत में पहले से ही तैयार एक बहुत बड़ा बाजार नजर आ रहा था। संरक्षित अर्थव्यवस्था के चलते यह बाजार उपभोक्ता सामग्री के विधिवर्धक रण पर जार नहीं दे पा रहा था अतः 1991 के बाद विदेशी निवेश खुल जाने व निजी उद्योग पर लगे विभिन्न नियन्त्रण समाप्त हो जाने पर भारतीय बाजार चहकने लगे और इनमें उत्पादों की किस्में अपना रंग दिखाने लगीं। साथ ही वित्तीय या बैंकिंग संशोधनों के बाद भारत के मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए महंगे या विलासितापूर्ण समझे जाने वाले उत्पाद (जैसे माटर, कार, स्कूटर, एफज, ए.सी. आदि) जीवन जीने के जरूरी सामान बनते गये। इसके समानान्तर ही स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों का भी वाणिज्यिकरण या बाजारीकरण होता चला गया और सार्वजनिक कम्पनियां भी निजी क्षेत्र के लिए खोली जाने लगीं जिसकी वजह से योजना आयोग की उपयोगिता धीरे-धीरे कम महसूस की जाने लगी। यहां तक कि पैट्रोल के दाम भी सीधे और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भावों से बांध दिये गये और ऐसा ही सोने के साथ ही किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सोने के दामों व विदेशी मुद्रा डालर के भावों को लेकर किया गया। डालर के भावों को तय करना रिजर्व बैंक ने छोड़ दिया और मुद्रा बाजार इसके भाव रूपये के मुकाबले तय करने लगा। अतः 2004 तक आते-आते ही योजना आयोग की आवश्यकता नगण्य जैसी हो गई लेकिन केन्द्र में इस वर्ष कांग्रेस नीत मनमोहन सरकार आ जाने की वजह से योजना आयोग बदस्तूर काम करता रहा। इसकी असली वजह यह थी कि 1991 में वित्त मन्त्री की हैसियत से डा. मनमोहन सिंह ने ही खुली अर्थव्यवस्था लागू की थी। वह चाह कर भी पं. नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग का भंग नहीं कर सकते थे। जबकि उनके शासनकाल में ही आयोग की पंचवर्षीय योजनाएं सीमित हो गई थीं। अतः 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमन्त्री बनते ही योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना कर डाली। इसका उद्देश्य राज्यों की सलाह से उनके लिए विकास योजनाओं के लिए धन मुहैया करना था परन्तु इसमें भी बाद में दिकतर्ते आने लगी थीं। जीएसटी लागू होने की वजह से राज्य केन्द्र से मिलने वाले अपने अंशदान पर निर्भर रहने लगे और गैर भाजपा राज्य शिकायत करने लगे कि जीएसटी में उनके हिस्से का धन मिलने में केन्द्र से बहुत देरी होती है। ये राज्य अपने साथ सोतेले व्यवहार की शिकायत करने लगे। वैसे मनमोहन सरकार में जब श्री मणिशंकर अर्यर पंचायत राज्य मन्त्री थे तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि राज्यों की विकास योजनाएं पंचायत स्तर से गांव के विकास की तैयार होते हुए राज्य के सकल विकास तक जानी चाहिए और फिर योजना आयोग को मंजूरी देनी चाहिए लेकिन नीति आयोग की बैठक का बिहिकार करना कोई हल नहीं समझा जा सकता। लोकतन्त्र में संवाद जहां रुकता है वहां कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है।—आदित्य नारायण



में भी हाइटैक उपकरण लगाए गए हैं। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हाल है जो भवन के बीचोंबीच बना हुआ है। इसी के ऊपर अशोक स्तम्भ लगा हुआ है। इस हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और देश के सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। अब संसद का आगामी सत्र इसी नई इमारत में होगा। यहाँ से कानून बनेंगे और यहाँ से देश चलेगा। नई संसद तैयार करने के पीछे यह तर्क भी था कि वक्त अब काफी बदल चुका है और गुलामी के प्रतीकों को बदलने का दौर भी आ चुका है। देश की अपनी स्वतंत्र छाप और लोकतंत्र की नई कहानी कहने के लिए नया संसद भवन अगली शताब्दियों के लिए एक नया रूप गढ़ने को तैयार है। जनता के लिए नए फैसले अब इसी भवन से निकलकर आएंगे। लोकतंत्र का प्रतीक नया संसद भवन केवल सत्ताधारी दल या विपक्षी दलों का नहीं है। यह देश की धरोहर है और यह हर भारतीय का है। बेहतर होता यदि इसके उदाघटन को लेकर सियासत नहीं होती। तब पूरे विश्व में एक जुट्टा का संदेश जाता। भारत के लोगों के लिए देश को नई संसद का मिलना एक भावनात्मक मुद्दा है। उनका स्वाभिमान बढ़ा है और भारतीय अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अन्य सभी मुद्दे उनके घलिए इस अवसर पर गौण हैं।

के लिए विशेष लाभ के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

बृष्ट : — स्वयं पर भरोसा रख्यों जनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करें। संगे—संबंधों में सरल व व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। अर्थाभाववश चिंता संभव।

मिथुन : — किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध से मन हतोत्साहित होगा। संबंधों के प्रति कुछ नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन में उत्साह का संचार होगा।

कर्क : — कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख—साधनों की लालसा बढ़े गी। शिक्षा—प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव।

सिंह : — किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। रोजगार में अति व्यस्तता रहेगी किंतु कायरे को समय से पूर्ण करें।

कन्या : — समस्याओं के समाधान हेतु मन नयी—नयी युक्तियों पर केंद्रित होगा। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें। छोटी—छोटी बातों पर क्रोधित न हो। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

मीन : — क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा में लापरावाही न करें। रोजगार में लाभ के नये अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

मायावती के सांसदों की चिंता

बहजन समाज पार्टी के सांसद चिंता में हैं। जैसे जैसे लोकसभा चनाय

बहुजन समाज पार्टी के सांसद चिंता में हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ रही है। मायावती इस जिद

पर अड़ी हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनके अकेले चुनाव लड़ने पर क्या होगा, इसका अंदाजा उनके सभी सांसदों को है। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था और उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता था, जबकि वोट 20 फीसदी के करीब मिले थे। अगले चुनाव में यानी 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया तो उनके 10 सांसद जीत गए। समाजवादी पार्टी पांच की पांच सीटों पर रह गई, लेकिन मायावती के सांसदों की संख्या जीरो से 20 हो गई। सोचें, 2014 में मायावती को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए सिर्फ दो साल हुए थे और उनका वोट पूरी तरह से उनके साथ था तब त्रिकोणात्मक मुकाबले में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। उनको राज्य की सत्ता से बाहर हुए 11 साल हो गए हैं और उनका वोट धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता गया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उनको सिर्फ 12.88 फीसदी वोट मिला और पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। ऐसे समय में अगर वे लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने जाती हैं तो सबको पता है कि नतीजे 2014 से भी खराब होंगे। सीटें तो नहीं मिलेंगी वोट भी 10 फीसदी से नीचे जा सकता है। तभी उनकी पार्टी के सांसद बेचौन हैं। वे चाहते हैं कि मायावती विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का हेस्सा बन कर चुनाव लड़ें। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो ज्यादातर सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं।

अमरोहा से पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने मायावती से गठबंधन में शामिल होने की अपील की है। उनको पता है कि पिछली बार समाजवादी से तालमेल होने की वजह से ही वे जीते थे और अगर मायावती अकेले लड़ें तो वे नहीं जीत सकते हैं। उनसे पहले बसपा के एक सांसद रितेश पांडेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश पादव से मुलाकात की थी। उनके सपा में जाने की चर्चा है। यह बसपा के सिर्फ दो सांसदों की कहानी नहीं है। पिछली बार बसपा की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े पूर्व सांसद कुशल तिवारी पार्टी छोड़ कर सपा में जा चुके हैं। अभी कई सांसद, कई पूर्व सांसद और बसपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कई नेता दूसरी पार्टियों में जाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है मायावती की पार्टी के कम से कम आठ सांसद ऐसे हैं, जो तालमेल नहीं होने की स्थिति में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने जा सकते हैं। ऐसे कई सांसद भाजपा और समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती लगभग निष्क्रिय रहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके वोट का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ। कहा जा रहा है कि वे किसी तरह के दबाव में हैं, जिसकी वजह से भाजपा को मजबूत चुनौती देने की रणनीति में विपक्ष के साथ शामिल नहीं हो रही हैं। उन्हें किसी बाहरी दबाव में निष्क्रिय रहना है या और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए कदम उठाना है, इसका

